

भारतीय जनता पार्टी

केन्द्रीय कार्यालय

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001

दूरभाष : 011-23005700, फ़ैक्स : 011-23005787

1 अप्रैल, 2013

प्रेस विज्ञप्ति

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह मध्य महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के दो दिवसीय दौरे पर आज औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद जिले से अपनी यात्रा शुरू करते हुए श्री सिंह ने किसानों और अन्य स्थानीय लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें क्षेत्र में सूखे की बिगड़ती स्थिति से अवगत कराया।

छड़ा चावनी और पिम्परी में किसानों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा, “ सूखा प्रभावित इलाकों में रह रहे किसानों को खेती में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। सूखे ने महाराष्ट्र के 11000 से ज्यादा गांवों और करीब 3500 से ज्यादा गांवों में 50 प्रतिशत फसलों को नुकसान पहुंचाया है।”

सूखा प्रभावित इलाकों में रह रहे किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ करने की मांग करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को कम से कम दो वर्षों के लिए सब्सिडीयुक्त बीज, खाद और ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर शत प्रतिशत सब्सिडी दी जानी चाहिए। “ किसानों को ब्याजमुक्त कृषि ऋण दिया जाना चाहिए और पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा सप्लाई किया जाना चाहिए। ”

केन्द्र द्वारा घोषित सूखा राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए श्री सिंह ने कहा, “ केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1200 करोड़ रुपये की सहायता काफी नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए खुद करीब 1800 करोड़ रुपये की मांग की थी। सरकार को सूखा राहत की राशि बढ़ानी चाहिए और इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय निगरानी दल गठित करना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए श्री सिंह ने कहा, “अनेक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 70000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और तब भी पिछले दस वर्षों में राज्य के कुल सिंचाई क्षेत्र में केवल 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।”

सूखा प्रभावित इलाकों में भूमिगत जल स्तर में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा,

“हालांकि सरकार ने महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण अधिनियम बनाया है लेकिन वह बहुमूल्य पानी का दुरुपयोग नहीं रोक सकी है। बहुमूल्य पानी आम आदमी और किसानों को तो नहीं मिल रहा है और अवांछित तत्व उसका लाभ उठा रहे हैं। अतः जल संबंधी अधिनियम में तत्काल संशोधन करने की जरूरत है ताकि पानी का दुरुपयोग रोका जा सके।”

उन्होंने कहा, “ सूखे ने गावों के गरीब लोगों और किसानों का रोजगार खत्म कर दिया है और बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सरकार को मनरेगा का विस्तार करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए और इसे कृषि के साथ जोड़ना चाहिए।

श्री सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र में सूखे का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।

(ओ पी कोहली)

मुख्यालय प्रभारी